and their families in a planned manner; and

(b) if so, the steps taken by Government to improve the working of the Board?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) It is a fact that meetings of this Board are not held regularly. No complaint has however, been received to the effect that it does not help ex-servicemen and their families in a planned manner.

(b) The matter will be brought to the notice of the State Soldiers', Sailors' and Airmen's Board, Bihar for necessary action.

खेती बाड़ी के सम्बन्ध में रेडियो कार्यक्रम

754. श्री महाराज सिंह भारती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गहन खेती के तरीकों और बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों तथा खेती के औजारों को प्राप्त करने के तरीकों तथा उनको प्राप्त करने के स्थानों और सिंचाई के साधनों तथा सिंचाई करने के समय के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के कृषि विभागों के सघन खेती और अधिक उपज देने वाली किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान करने के लिये 1966–67 में आकाशवाणी के 10 केन्द्रों में 10 फार्म और गृह प्रसारण यूनिटें स्थापित की गई । ये यूनिटें तरीकों और समस्याओं की समानता के आधार पर चुने गये छोटे, ठोस और समरूप कृषि-प्रधान क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये स्थापित की गई हैं । ये कार्यक्रम अधिकतर खेती सम्बन्धी समस्याओं के बारे में होते हैं और बहुत अधिक संख्या में प्रगतिशील किसान अब इन प्रसारणों में भाग ले रहे हैं । आकाशवाणी के केन्द्रों और किसानों के बीच विचारों के आदान-प्रदान में ये काफी सहायक हो रही हैं ।

2. चालू साल में इस प्रकार की 6 और फार्म और गृह यूनिटें खोलने का विचार है । तब इन यूनिटों की संख्या 16 हो जाएगी । चालू योजना अवधि में ये 16 यूनिटें लगभग 130 जिलों में 3 करोड़ 25 लाख एकड़ क्षेत्र कवर करेंगी ।

3. फार्म और गृह यूनिटों का मुख्य उद्देश्य सघन खेती और अधिक उपज देने वाली किस्मों सम्बन्धी विविध कार्यक्रमों, जिनमें अच्छी किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों और खेती के आधुनिक औजारों का प्रयोग करना आदि शामिल है के बारे में जानकारी देना है । इन्हें प्राप्त करने के बारे में इन कार्यक्रमों में सामान्य रूप से जानकारी दी जाती है । किसानों को इस बारे में विशिष्ट जानकारी राज्यों के विस्तार विभागों द्वारा दी जाती है । विभिन्न फ़सलों के बारे में सिंचाई के साधनों तथा सिंचाई करने के समय के बारे में सूचनाएं देना भी इन कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण अंग है ।

26 जनवरी, 1967 से दिल्ली टेलीविजन केन्द्र से केन्द्रीय शासित दिल्ली क्षेत्र के कृषकों के लिए एक अर्ध-साप्ताहिक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । गांवों में 80 टेलीविजन सेट लगाए गए हैं और इन कार्यक्रमों में मुख्यतः कृषकों को सघन खेती और अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी देने और समझाने पर जोर दिया जाता है ।

रक्सौल में आकाशवाणी केन्द्र

755. श्री के० एम० मधुकर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल में दस किलोवाट का एक प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का है ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) पटना का मीडियम वेव ट्रांसमीटर पहले ही से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है। भारत-नेपाल सीमा को और अधिक प्रसारण देने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर दरभंगा में और एक ऊंची शक्तिवाला ट्रांसमीटर गोरखपुर में लगाने का प्रस्ताव है।

विदेशों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार

756. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह: क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार नहीं किया जाता क्योंकि वहां के लोगों को हिन्दी नहीं आती ;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों को अपने पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में भेजने की व्यवस्था की है ;

(ग) यदि हां, तो जुलाई, 1966 से फरवरी, 1967 तक इस प्रकार के कितने पत्र भेजे गये ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चामला): (क) जी हां। विश्वास-पत्र आदि जैसे औपचारिक पत्रों को छोड़कर, विदेश-स्थित हमारे मिशन दूसरे देशों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार नहीं करते। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां के लोगों को हिन्दी का कोई ज्ञान नहीं होता और इसलिए भी, कि हमारे पास ऐसे कर्मचारियों की कमी है जिन्हें अच्छी तरह हिन्दी आती हो और जो अंग्रेजी की तरह ठीक हिन्दी में भी अपने आपको अभिव्यक्त कर सकते हों। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय में भी ज्यादातर अंग्रेजी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं। ऊपर बताई गई परिस्थितियों में अभी अंग्रेजी मूल पाठ के साथ हिन्दी अनुवाद भेजने से कोई फायदा नहीं होगा ; बल्कि दूसरी तरफ़ इससे हमारे ऊपर अमले का और अन्य ज़रूरी बातों का विदेशी मुद्रा में अनावश्यक खर्च बढ़ जाएगा।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

सैनिक कर्मचारियों द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन

757. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सेवा निवृत सैनिक कर्मचारियों द्वारा सरकारी भेदों वाली पुस्तकों के कुछ प्रकाशन के बारे में कोई आचरण संहिता तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं। सरकारी गोपनीय अधिनियम के उल्लंघन करने पर सेवा निवृत सैनिक कर्मचारियों के विरुद्ध उसी तरह कार्यवाही की जाती है जिस तरह कि अन्य नागरिकों के विरुद्ध किया जाता है। सरकार की अनुमति लिए बिना सेवा निवृत सैनिक कर्मचारी कोई पुस्तक आदि न लिखे–